35

प्रशासन में नैतिकता, मूल्य तथा उत्तरदायित्व (ETHICS, VALUES AND ACCOUNTABILITY IN ADMINISTRATION)

लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के विकास में एक विरोधाभास दिखाई देता है। जैसे-जैसे जनता की सेवा करने के लिए राज्य अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जाता है, अधिक से अधिक लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि सामाजिक कल्याणकारी राज्य ने उनको पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। ज्यों-ज्यों लोक-प्रशासन की मशीनरी फैलती है और अधिक जटिल होती जाती है, त्यों-त्यों इसको ठीक प्रकार से जवाबदेह बनाने की आवश्यकता अधिक तीव्रता से अनुभव की जा रही है। आधुनिक समय में लोकप्रशासन के विद्वानों में पर्याप्त सहमति है कि आज सरकारी प्रशासन की प्रमुख समस्या कुशलता प्राप्त करना नहीं अपितु जवाबदेही निश्चित करना है; कुछ विद्वान इसको लोकप्रशासन की उत्कृष्ट समस्या मानते हैं।[1]

एक लोकतांत्रिक सरकार में, धारणा यह है कि लोक-अधिकारी सरकार में जनता की सेवा के लिये कार्य करते हैं। चूंकि जिस प्रकार का कार्य लोक-अधिकारी करते हैं और जिस प्रकार की सत्ता का प्रयोग वे करते हैं, इसलिए जवाबदेही को निर्धारित करने की समस्या गम्भीर बन जाती है। आज लोक-प्रशासन विधानमंडल द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने और कानूनों को कार्यान्वित करने का कार्य ही केवल नहीं करते, अपितु वे समझबूझ कर कानून भी बनाते हैं और कानूनों पर न्याय-निर्णय भी देते हैं। विधानमंडल जो कानून बनाता है वे केवल मोटे लक्ष्यों को निश्चित करते हैं, विधान में जो लुप्तांश रह जाते हैं उनको भरने के लिए विस्तृत नियम, अधिनियम तथा उपविधि बनाने का कार्य प्रशासकों को सौंपा जाता है ताकि कानूनों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया सरल हो सके। प्रशासकों को कभी-कभी यह कहा जाता है कि वे कुछ मुद्दों की व्याख्या करें तथा न्यायनिर्णय करें।" अतः 19वीं शताब्दी की कानूनों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने की समस्या आज नीति-निर्णय और नीति-न्यायनिर्णय पर नियंत्रण रखने के अधिक जटिल कार्य में विकसित हो गई है। अतः प्रशासनिक जवाबदेही की धारणा का अर्थ विस्तृत कर दिया गया है और परिणामस्वरूप इसके आयाम बढ़ गये हैं।"[2]

लोक-अधिकारियों की अनुसेवा निश्चित करने के लिए जवाबदेही, उत्तरदायित्व, प्रत्युत्तरदायिता तथा नियंत्रण जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रत्युत्तरदायिता (Responsiveness)

इसका शाब्दिक अर्थ है "प्रत्युत्तरदायी होने की स्थिति", अर्थात् उत्तर देना, जवाब देना। लोकतंत्र में नागरिक लोक-अधिकारियों से अपनी प्रार्थनाओं और मांगों के प्रति प्रत्युत्तरदायी होने की आशा करते हैं। एक नागरिक जो अपनी सरकार से कुछ चाहता है, का अधिकार है कि उसे जवाब दिया जाये और उसे मांगों का एक वैध स्रोत माना जाये। परन्तु कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब नागरिक तथा हित-समूह बहुत अधिक प्रत्युत्तरदायित्व की आशा करते हैं। वे चाहते हैं कि प्रशासन उनके पक्ष में कार्यवाही करें भले ही उसके लिये विधि की शंकास्पद व्याख्या करनी पड़े या वह दूसरे लोगों के लिये हानिकारक हो। प्रत्युत्तरदायिता अच्छी सरकार के लिये प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। "लोकतंत्र में सरकार तथा लोक-प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वे नागरिकों को लोकसेवा प्राप्ति के लिये अपनी मांगों को व्यक्त करने से रोकें, न ही लोक-अधिकारियों को यह अधिकार है कि वह किसी को भी अपनी मांगों के सम्बन्ध में

सुनवाई से इन्कार करें। परन्तु इन संस्थानों को यह अधिकार तथा कर्तव्य है कि सभी ऐसी मांगें रद्द
दें जो विधि पर आधारित नहीं।"[3]

उत्तरदायित्व (Responsibility)

प्रायः उत्तदायित्व तथा जवाबदेही शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए किया जाता है। जवाबदे
उत्तरदायित्व की वैधानिक तथा पदानुक्रम स्थिति को कहते हैं, जबकि उत्तरदायित्व का अभिप्राय यह
कि लोक-अधिकारी उचित प्रशासन और नीति के प्रत्यक्ष और परोक्ष मूल्यों का आदर करेंगे। उत्तरदा
(जिम्मेदार) लोक-अधिकारी विधि को जानते हैं और उनको अपने कार्यक्रमों के उचित प्रशासन में विश्
होता है। जिस राजनीतिक संसार में वे कार्य करते हैं उसकी मांगों, कोलाहल तथा खलबली में यह भूल
प्रतिरोधक सिद्ध होते हैं। लोक-अधिकारियों के व्यवहार तथा भूमिका की यह धारणा लोक-नौकरशाही
सम्बन्ध में प्राचीन विचारों के समान है जिसमें यह समझा जाता था वे विधि के उचित प्रशासन के लि
कार्य करते हैं। इस धारणा के अधीन निरन्तर जनमत की ओर ध्यान दिये बिना ही प्रशासक निर्णय क
सकते हैं। विशेषज्ञता तथा विधि ही लोक-सेवा के प्रचालन का आधार बन जाते हैं।

जवाबदेही (Accountability)

ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजी भाषा में जवाबदेह (Accountable) शब्द का प्रयोग प्रथम
1583 वर्ष में वित्तीय संदर्भ में किया गया था।[4] आज भी वित्तीय जवाबदेही धारणा का महत्वपूर्ण भाग है
जो एक समाविष्ट धारणा है और इसमें सरकार द्वारा की जाने वाली सभी क्रियायें आ जाती हैं। जवाबदेह
होने का अर्थ है सफाई पेश करने के लिये उत्तरदायी। अतः जवाबदेही का अर्थ है कि प्रशासन को ज
सत्ता सौंपी गई है उसके प्रयोग के लिए जवाबदेह होना। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जवाबदेही कि
के लिये ? इसको निष्पादन से जोड़ा गया है, यह उपलब्धि-उन्मुखी है। ".....प्रशासनिक जबाबदेही एक
संगठनात्मक आवश्यकता है क्योंकि सर्वप्रथम, यह लक्ष्यों के संदर्भ में इसके निष्पादन के मूल्यांकन क
प्रयास करती है। लक्ष्य को निश्चित कार्यों और दायित्वों में विभाजित किया जाता है, और प्रशासकों क
व्यक्तिगत रूप में पूछा जाता है कि वे बतायें कि वे किस प्रकार अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं
जवाबदेही प्रशासनिक दायित्व की सहगामी है, दूसरे शब्दों में, सिक्के का दूसरा पहलू है.....यह किसी
संगठन के अंतर्भूत पदसोपान, नियंत्रण क्षेत्र, आदेश की एकता, निरीक्षण आदि सभी धारणायें जवाबदेह
को प्रोत्साहित करने और लागू करने के यंत्र हैं। वार्षिक बजट भी यही करता है.....जवाबदेही का लाभ
तभी होता है जब इसको दृढ़ता से और निकट से संगठन के लक्ष्यों और मूल कार्यों से जोड़ दिया जाए
है।"[5] प्रशासनिक जवाबदेही उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलन को निश्चित करने के साथ-साथ संगठनात्मक
लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करती है।

जवाबदेही के उपकरण (Tools of Accountability)

लोकतंत्र तथा कुशलता और प्रभावकारिता के हित में यह अनिवार्य है कि लोक-नौकरशाहियों को
सीमित रखने के लिये उचित उपकरण या नियंत्रण ढूँढे जायें। नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं बाह्य तथा
भीतरी। प्रोफेसर फाईनर (Prof. Finer) के अनुसार, जवाबदेही को लागू करने का सर्वोत्तम तरीका ऐसे
संस्थानों का विकास करना है जो लोक-नौकरशाही के कार्यों की सक्रिय ढंग से निगरानी करें और ऐसे
अधिकारियों को दण्ड दें जो कुशासन के अपराधी हों। अपनी एजेन्सी से बाहर के लोगों के बल और
निगरानी के कारण प्रशासक उचित व्यवहार करते हैं। उनकी धारणा यह है कि जो लोग सरकार के
भीतर काम करते हैं वे उनसे भिन्न नहीं जो शेष समाज में रहते हैं। लाभ की इच्छा जैसे नियंत्रणों के
अभाव में नीति-निर्माताओं के लिए आवश्यक है कि वे औपचारिक यंत्रावली के माध्यम से लोक प्रशासन
के निष्पादन की निगरानी करें।[6]

विधानमंडल के प्रति कार्यकारिणी का उत्तरदायित्व, विधानमंडल की निगरानी, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, लेखापरीक्षण, मंत्रालयों में वित्तीय परामर्श व्यवस्था आदि वाह्य औपचारिक नियंत्रणों के उदाहरण हैं। भीतरी औपचारिक नियंत्रण संगठनात्मक माध्यमों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जिनके उदाहरण हैं पदसोपान, परीक्षण, नियंत्रण, नियंत्रण क्षेत्र, आदेश की एकता, परीक्षण आदि। व्यवहार में इनके पूरक व इनको दृढ़ता प्रदान करने वाले वाह्य अनौपचारिक यंत्र भी समाज में होते हैं, जैसे लोक-प्रसारण, राजनीतिक दल, हित समूह, राजनीतिक तथा निर्वाचन प्रक्रिया, निगरानी संगठन आदि।

दूसरी ओर कार्ल फ्रेडरिच (Carl Friedrich) का मत है कि प्रशासकों में यथा– उचित मूल्यों का अंतर्निवेशन नौकरशाही पर मुख्य रोक का कार्य करता है। इस विचारधारा के अनुसार यदि लोक-अधिकारियों में दृढ़ लोकतांत्रिक तथा प्रशासनिक मूल्यों का अभाव है तो औपचारिक संस्थात्मक चैक प्रायः असफल रहेंगे।[7] सारांश यह है कि प्रशासकों में भीतरी कम्पास अथवा मूल्यों को होना अनिवार्य है जो उनको ठीक दिशा की ओर संकेत करे।

सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा मूल्य (Integrity, Ethics and Values)

ऊपर जो दूसरा दृष्टिकोण दिया गया है जिसका नेतृत्व कार्ल फ्रेडरिच (Carl Friedrich) करते हैं, वह हमें लोकसेवा में सत्यनिष्ठा, नैतिकता तथा मूल्यों के प्रश्न पर ले आता है।

सामान्यतः लोकसेवा को एक उत्कृष्ट तथा गौरवमय व्यवसाय समझा जाता है। यह सेवा राष्ट्र के हित में है, और प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य की सेवा से बढ़ कर कोई और सेवा नहीं हो सकती। जो लोग लोकसेवा में जाना स्वीकार करते हैं वे धनी तथा प्रसिद्ध होने की सम्भावना नहीं रखते। उनमें से अधिकतर लोगों की लोकसेवा के मूल्यों में मौलिक निष्ठा होती है। अन्य लोकसेवा में कुछ समय कार्य करने के उपरांत ऐसी निष्ठा विकसित करते हैं। प्राचीन यूनानी नगर राज्य में एक नागरिक केवल राज्य सेवा में ही अपनी सम्पूर्णता को प्राप्त करता था। यह नगर राज्य या "पोलिस" ही था जिसमें अच्छा जीवन सम्भव था। उसकी आत्मसम्पूर्णता तथा नगर-राज्य में सार्वजनिक जीवन को योगदान एक ही सिक्के के दो पहलू थे। हमें लोकसेवा में किस प्रकार के व्यक्ति चाहिये ? एम० आर० पिन्टों (M. R. Pinto), जे० जी० हालैण्ड की कुछ पंक्तियों को दुहराते हैं[8] :

भगवान, हमें व्यक्ति दो।
भगवान, हमें व्यक्ति दो ! आज की तरह का समय दृढ़ मस्तिष्कों, बड़े हृदयों, सत्य विश्वास तथा तत्पर हाथों की मांग करता है,
व्यक्ति जिनको पद की लालसा नष्ट नहीं करती,
व्यक्ति जिनको पद के लाभ खरीद नहीं सकते,
व्यक्ति जिनकी धारणायें और अन्तरात्मा है,
व्यक्ति जिनका है सम्मान, व्यक्ति जो झूठ नहीं बोलेंगे,
(God, give us men !
God, give us men! A time like this demands strong minds,
great hearts, true faith and ready hands;
Men whom the lust of office does not kill;
Men whom the spoils of office cannot buy;
Men who possess opinions and a will;
Men who have honour; men who will not lie;)

निसंदेह ! आज के संसार में लोकसेवा में हमें ऐसे व्यक्ति ही चाहियें। प्रशासकों को "सर्वव्यापी मूल्यों जैसे बुद्धिमता तथा श्रद्धा, ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा, मानवीय हितों के प्रति भक्ति, साथ ही साथ

वे परम्परायें जो एक विशेष सभ्यता की विशेष सांस्कृतिक धारा में पसंद की जाती हैं, का एकीकरण दिखाना होगा। प्रशासकों को एक मिशन की भावना, अन्तर्सम्बन्धों की समझ और समूचे लक्ष्यों तथा मूल्यों की विवशकारी अनुभूति विकसित करनी होगी।"[9]

आज का राज्य कल्याणकारी राज्य से भी आगे बढ़ गया है। यह पुनः विभाजक राज्य है या प्राकृतिक न्याय राज्य है, जिस में स्वतन्त्रता प्राप्ति, न्याय, समानता और सम्मान तथा सम्पूर्णता को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। इस प्रकार के उद्देश्य जनसेवा पर बल देते हैं और अनिवार्य रूप से मूल्यों, नियमों तथा नैतिकता के प्रश्नों को सामने ले आते हैं। आधुनिक प्रशासन की बढ़ती हुई जटिलता के लिए व्यवसायिक ज्ञान तथा विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इसको सेवा की दिशा में चलना आवश्यक है, और सामान्य हित के प्रति वचनबद्धता तथा भक्ति की भावना होनी चाहिये। इसलिये प्रशासनिक व्यवहार तथा इसको प्रभावित करने वाले मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हैं।

मूल्य मानव व्यवहार के पीछे प्रचालन शक्ति हैं। मनुष्य जो कुछ करता है वह उसकी मूल्य संरचना के संदर्भ में समझा जा सकता है। मूल्य ही मनुष्य के नियम, मानक तथा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने या कार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के चयन में भी मूल्य मनुष्य की सहायता करते हैं।

मूल्य प्रेरणा, इच्छा या आवश्यकता नहीं, कुछ और है। इसको प्रेरणा शक्ति के साथ अभिलाषणीय की धारणा कहा गया है। मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है "एक प्रत्यक्ष या परोक्ष धारणा, एक अभिलाषणीयों का समूह जिनकी अपनी पृथक् विशेषता या व्यक्तित्व है जो कार्य के उपलब्ध साधनों, शैलियों तथा लक्ष्यों में चयन को प्रभावित करता है।"[11]

मूल्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, समूह से दूसरे समूह और एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भिन्न-भिन्न होते हैं। वे जड़ अथवा स्थायी नहीं होते। वे समय के साथ तथा अन्य कई तत्वों के प्रभाव जैसे– राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक या सैद्धांतिक परिवर्तन आदि से परिवर्तित होते हैं। मूल्यों का संस्कृति के साथ बड़ा निकट का सम्बन्ध होता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं : सामाजिक मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य, संस्थात्मक मूल्य, संरचनात्मक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, व्यवसायिक मूल्य तथा व्यक्तिगत मूल्य। सामान्यता प्रत्येक व्यक्ति सांस्कृतिक प्रभावों, विज्ञान तथा नवीनताओं, धर्म तथा जातीय प्रभाव और जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी मूल्य व्यवस्था निर्मित करता है।[12]

कभी-कभी मूल्यों में टकराव भी आ जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य उसके व्यवसायिक या संस्थात्मक मूल्यों से टक्कर खा सकते हैं। लोक-अधिकारियों को इस प्रकार की दुविधा कई बार झेलनी पड़ती है। लोकसेवा में मूल्य-समूहों के टकराव के कारण नैतिक समस्यायें खड़ी हो जाती हैं। क्या एक अधिकारी अपने व्यक्तिगत मूल्य का पालन करेगा जो स्वयं परिवार तथा मित्रों के प्रति उत्तरदायित्व का समर्थक है ? इसकी सार्वजनिक हित या व्यवसायिक उत्तरदायित्वों से टक्कर हो सकती है। "इससे जो जटिल प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, वे हैं : व्यक्ति को उचित कार्य करना चाहिये, परन्तु उचित क्या है ? इसकी परिभाषा कौन करेगा और किस के लिए ? और किस उद्देश्य के लिए ? व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिये, परन्तु कैसे और कहाँ तक ? व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये, परन्तु किसके प्रति और कैसा" ?[13] व्यक्ति को सार्वजनिक हित में कार्य करना चाहिये, परन्तु सार्वजनिक हित की परिभाषा कौन करेगा ?

लोकसेवा में आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक या संस्थात्मक मूल्यों में समझौता होना चाहिये। पीटर ड्रकर (Peter Drucker) के अनुसार, "संस्थात्मक तथा व्यक्तिगत मूल्यों का संगम ही प्रशासन का सर्वोत्कृष्ट सिद्धान्त बन जाता है।"[14] शैलियों से बढ़ कर मूल्य ही प्रशासकों के कार्यों के अंतिम निर्णायक होते हैं। "प्रशासक वह व्यक्ति है जो निर्णय करता है। यदि वह निर्णय करने में

...रहता है, तो वह प्रशासक नहीं, केवल पद अधिकारी है। प्रशासक के रूप में उसके चरित्र पर ...दबाव रहता है। यदि वह किसी से डर जाता है, तो उसका नाश होगा। यदि वह किसी की आलोचना ...बदनामी व निंदा भी सम्मिलित है, सहन नहीं कर सकता, तो वह भटक गया। यदि वह समान लोगों ...व्यवहार नहीं दे सकता तो वह नष्ट हो गया। आज प्रशासक को इस व्यवहारिक तथा दर्शनात्मक ...ता के सामंजस्य की आवश्यकता है, जिसमें अनिवार्य नैतिक गुण हों जो उसे बनाये रखें, ताकि वह ...कर्तव्यों का अच्छी प्रकार पालन कर सके। हचिंस (Hutchines) यह कहते हुए समाप्त करते हैं ...प्रशासक के पुरस्कार सार्वजनिक स्मारक, धार्मिक अनुष्ठान तथा आनन्दित लोगों के द्वीपों तक एक ...जक यात्रा भले ही ना हो। इन वस्तुओं की चिंता उसे कदापि नहीं करनी चाहिये। उसको संतुष्टि, ...वह असफल भी हो जाता है, इस बात से मिलेगी कि उसने मस्तिष्क के कठिनतम कार्यों में से एक को ...और करने का प्रयास किया और जो सब से अधिक चुनौतीपूर्ण मानवीय कार्यों में से एक था।"[15]

मूल्य व्यवस्था अमुक तत्त्वों के आधार पर बनती है :

1. जिन मूल्यों का परिवार के भीतर प्रारम्भिक शिशुकाल में अंतर्निवेशन किया जाता है
2. शिक्षा
3. प्रशिक्षण
4. सार्वजनिक मीडिया या प्रसारण जैसे सिनेमा, टी. वी., समाचार पत्र तथा पुस्तकें
5. तकनीकी विकास घटनायें, तीव्र गति सार्वजनिक परिवहन, कम्प्यूटर तथा गर्भ-निरोधक उपचार
6. पर्यावरण
7. राजनीतिक व्यवस्था
8. समुदाय के भीतर धार्मिक तथा नैतिक विचार-चिंतन
9. नैतिक वातावरण
10. राष्ट्रीय संस्कृति, जाति स्वभाव तथा पर्यावरण

...बदेही संस्कृति से जुड़ी हुई (Accountability Culture Oriented)

प्रशासनिक जवाबदेही की धारणा संस्कृति से जुड़ी होती है। प्रशासनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में ...ता की आशाओं की प्रकृति तथा मात्रा के साथ-साथ इस धारणा में भी परिवर्तन होता है। बहुत सीमा ...यह किसी राजनीतिक व्यवस्था का सांस्कृतिक वातावरण ही होता है जो उसके संदर्भ में प्रशासनिक ...बदेही के अर्थ और जवाबदेही को परिभाषित करती है। सार्वजनिक नैतिकता तथा प्राशसनिक ...चार के प्रति समाज की वचनबद्धता एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है। एक समाज में ...मों का उल्लंघन या रिश्वत स्वीकार करना अपराध समझे जाते हैं, परन्तु किसी दूसरे समाज में इसी ...र्य को लोक-अधिकारियों से काम लेने के लिए एक स्वीकृत व्यवहार मान लिया जाता है। "यह ...स्कृतिक परम्परा और लोक-अधिकारियों तथा सामान्य जनता के बीच पारस्परिक आकांक्षायें ही होती ...जो प्रशासनिक जवाब देही की सीमाओं को निश्चित करने की ज़िम्मेदार होती है।"[16] ब्रिटेन, फ्रांस ...जर्मनी में प्रशासनिक वर्ग को जो सम्मान तथा उच्च स्थान प्राप्त है वह आस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य ...रिका से भिन्न है, जहाँ इतना ऊँचा सम्मान व स्थान नहीं है। इस भेद का कारण उनके भिन्न-भिन्न ...हास और संस्कृतियाँ हैं। इसी प्रकार जिन समाजों की ठोस या जड़ संरचना होती है, जो परिवार या ...की सदस्यता पर आधारित होते हैं, उनमें यदि कोई लोक-अधिकारी परिवार या रक्त सम्बन्धों की ...ता की अवहेलना करते हुए न्याय तथा औचित्य जैसे मूल्यों का समर्थन करने का प्रयास करेगा, तो ...लोग बेमेल व्यक्ति समझेगें। किस सीमा तक और किस ढंग से प्रशासनिक जवाबदेही को प्राप्त किया ...गा, यह एक वैधानिक-संस्थात्मक प्रबन्धों तथा राजनीतिक संस्कृति का मुददा है।

जवाबदेही की सीमायें (Limitations to Accountability)

जवाबदेही की प्रक्रिया का कार्यान्वयन इतना सरल तथा सुगम नहीं है इस पर कई अंकुश हैं:

1. किसी व्यक्ति की व्यवसायिक नैतिकता की उसकी प्रशासनिक नैतिकता से टक्कर हो सकती है। ऐसा विशेषकर वहाँ होता है जहाँ सरकारी संगठनों में विशेषज्ञों या व्यवसायिक व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो। यहाँ प्रशासनिक जवाबदेही पर विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार की गई आंतरिक मूल्य संरचना का अंकुश होता है।[17] उदाहरणतया, सरकारी हस्पतालों में नियुक्त किये गये डाक्टरों की प्राथमिक भक्ति चिकित्सा व्यवसाय के नियमों के प्रति होती है। उनके द्वारा ऐसे नियमों का विरोध उचित होगा जो उनके रोगियों के साथ व्यवसायिक तथा नैतिक सम्बन्धों से टक्कर खाते हैं।

2. उन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों जो उत्पादन या आर्थिक या वाणिज्य कार्यों में लगे हैं, कि जवाबदेही उन प्रशासकों की जवाबदेही से भिन्न होगी जो एक प्रारूपी सरकारी विभाग में कार्य करते हैं। क्योंकि उन प्रबन्धकों को व्यापार की लाइन पर कार्य करना होता है और निजी क्षेत्र के साथ होड़ करनी पड़ती है।

3. कभी-कभी मजदूर संगठनों की कार्यवाही विभागीय नियमों, अर्धनियमों या बजट सम्बन्धी नियमों के प्रति जवाबदेही को सीमित करते हैं।

4. चूंकि जबाबदेही संस्कृति से जुड़ी होती है (जैसा ऊपर कहा गया है) यह एक राजनीतिक व्यवस्था के सांस्कृतिक वातावरण के भीतर कार्य करती है। अतः बहुत हद तक प्रशासनिक जवाबदेही की प्रकृति तथा व्याख्या इसी द्वारा निश्चित की जाती है।

5. प्रशासनिक जबावदेही किसी देश की राजनीतिक संरचना से प्रभावित होती है। उदाहरणतया एक संघीय व्यवस्था में प्रशासनिक जवाबदेही की प्रकृति तथा सीमा उस से भिन्न होंगे जो एकात्मक सरकार व्यवस्था में होते हैं। भारत जैसे देश में यह समस्या और भी जटिल हो जाती है क्योंकि यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है परन्तु इनको राज्य सरकारों, स्वायत्त संगठनों, सरकारी निगमों आदि के अधीन कार्य करना पड़ता है। वे इन संगठनों के प्रति पूरी तरह जवाबदेह नहीं हो सकते क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार की अनुशासन शक्ति के अधीन रहते हैं।

6. प्रशासनिक जवाबदेही उन स्थितियों तक सीमित रहती है जिनको "प्रशासनहीनता" (Non-administration) कहा जा सकता है। "वास्तव में वहाँ प्रशासनिक जवाबदेही लागू करना बड़ा कठिन हो जाता है जहाँ प्रशासन की गतिविधि नाममात्र भी नहीं है। ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जहाँ औपचारिक प्रशासनिक संस्थानों तथा कार्यप्रणालियों की अवहेलना करके निर्णय किये जाते हैं, वहाँ ठीक प्रशासनिक जवाबदेही की आशा करना लगभग असम्भव है। विश्व में ऐसी भी प्रशासनिक व्यवस्थायें हैं जहाँ कार्य करने के लिये सकारात्मक प्रोत्साहन नहीं है, और कार्य ना करने के नकारात्मक प्रोत्साहन बहुत होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासनिक जवाबदेही प्राप्त करना कठिन होता है।"[18]

जवाबदेही के रूप (Forms of Accountability)

जवाबदेही के कई स्वरूप हैं परन्तु वे एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। जवाबदेही औपचारिक भी हो सकती है अर्थात् संस्थात्मक या अनौपचारिक भी हो सकती है अर्थात् लोकतांत्रिक और नैतिक। जवाबदेही के और भी स्वरूप हो सकते हैं जैसे– राजनीतिक जवाबदेही, प्रशासनिक जवाबदेही, विधानमंडलीय जवाबदेही, न्यायिक जवाबदेही आदि।